

## चुनावी बॉण्ड

### प्रलिस के लयल:

चुनावी बॉण्ड, राजनीतलक दल, ललगुुु का प्रतनलधलतलव अधनलयलम 1951

### मेनुस के लयल:

चुनावी प्रकुरयल पर चुनावी बॉण्ड का प्रभाव, नीतयलुुु के नरलमाण और उनके कारयानवयन से उत्पनन मुदुदे

## चरुुा में कुुुुु?

हाल ही में [भारतीय स्टेट बैंक \(SBI\)](#) ने डेटा रलुुुुरतगल साझा की जसलमें बताया गया है कल चुनावी बॉण्ड (EB) के माध्यम से राजनीतलक दलुुुु को दान की गई राशल 10,000 करोड रुपए का आँकडा पार कर चुकी है ।

- जुलाई 2022 में आयोजतल चुनावी बॉण्ड की 21वीं बकलरी में पारुतयलुुु को चुनावी बॉण्ड खरीद से 5 करोड रुपए मलल ।
- पारुतयलुुु द्वारा एकतुर की गई कुल राशल वलरुष 2018 में चुनावी बॉण्ड योजना शुरु होने के बाद से 10,246 करोड रुपए हो गई है ।

## चुनावी बॉण्ड:

### ■ परचलय:

- भारतीय स्टेट बैंक इन बॉण्डस को जारी करने और भुनाने (Encash) के लयल अधकुत बैंक है ।
- चुनावी बॉण्ड दाताओुुु द्वारा गुप्त रूुु से खरीदुे जाते हैं और ये बॉण्ड जारी करने की तारीख से पंदरह दनलुु तक वैध रहते हैं ।
- ःदृण साधनुुु के रूुु में इनुुुें दानदाताओुुु द्वारा बैंक से खरीदा जा सकता है और राजनीतलक दल उनुुुें भुना सकते हैं ।
- इनुुुें केवल एक पातुर [राजनीतलक पारुती](#) द्वारा बैंक के अपने खाते में जमा करके भुनाया जा सकता है ।
- चुनावी बॉण्ड SBI द्वारा बनल कसलल अधकुतम सीमा के 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड रुपए के गुणकुुुु में जारी कयल जाते हैं ।
- बॉण्ड कसलल भी वुुकतुल (जुुु भारत का नागरकल है) द्वारा जनवरी, अपुरैल, जुलाई और अकुतुुुबर के महीनुुुु में प्रतुुुेक दस दनलुु की अवधल हेतु खरीद के लयल उपलबुध होते हैं, जैसा कल कुेंदुर सरकार द्वारा नरलदशलट कयल गया है ।

### ■ पातुरता:

- केवल लुक प्रतनलधलतलव अधनलयलम, 1951 की धारा 29 ए के तहत ऐसे पंजीकुत राजनीतलक दल जनुुुुुनेलुकसभा या वधलानसभा के पछले आम चुनाव में डाले गए वुुुुुु का कड-से-कड 1% वुुुुुु प्राप्त कयल है, वे चुनावी बॉण्ड प्राप्त करने के लयल पातुर हैं ।

## चुनावी बॉण्ड भारत के लयल चुनुुुुती का वषलय:

### ■ मूल वचलार के वषलरलत:

- चुनावी बॉण्ड योजना की मुख्य आलुकना यह की जाती है कल यलहअपने मूल वचलार यानल चुनावी फंडगल में पारदरशतल लाने के ठीक वषलरलत काम करता है ।
  - उदाहरण के लयल आलुककुुु का तरुक है कल चुनावी बॉण्ड की गुडनामी केवल जनता और वषलकुषी दलुुु तक की सीडतल होती है ।

### ■ जबरन वसुुुुी की संभावना:

- चुुुकल इस तरह के बॉण्ड सरकारी सुवामतलव वाले बैंकुुु (SBI) के माध्यम से बेचे जाते हैं, ऐसे में कुडल आलुककुुु का डानना है कल सरकार इसके माध्यम से यह जान सकती है कल कुुुुन ललग वषलकुषी दलुुुु को वतलतडुुषण प्रदान कर रहे हैं ।
  - परणलडसुवरूुु यह प्रकयल केवल ततकालीन सरकार को ही धन उगाही की अनुडतल देती है और इस प्रकार से सतुुुुधारी पारुती को अनुचतल ललड प्रदान करती है ।

### ■ लुकततुर के लयल चुनुुुुती:

- वतलत अधनलयलम 2017 में संशुुुुधन के माध्यम से कुेंदुर सरकार ने राजनीतलक दलुुुु को चुनावी बॉण्ड के जरलयल प्राप्त राशल का खुलासा करने

से छूट दी है।

- इसका मतलब है कि मतदाता यह नहीं जान पाएंगे कि किस व्यक्ति, कंपनी या संगठन ने किस पार्टी को और किस हद तक वित्तपोषण किया है।

◦ हालाँकि प्रतनिधि लोकतंत्र में नागरिक अपना वोट उन्हें देते हैं जो संसद में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे।

#### ■ 'जानने के अधिकार' से समझौता:

◦ **भारतीय सर्वोच्च न्यायालय** ने यह स्वीकार किया है कि 'जानने का अधिकार' विशेष रूप से चुनावों के संदर्भ में **भारतीय संविधान** के तहत **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 19)** का एक अभिन्न अंग है।

#### ■ स्वतंत्र और नष्पिक्व चुनावों के खिलाफ:

◦ चुनावी बॉण्ड नागरिकों को इस संदर्भ में कोई वविरण नहीं देते हैं।

◦ उक्त गुमनामी उस समय की सरकार पर लागू नहीं होती है, जो कि **भारतीय स्टेट बैंक (SBI)** से डेटा की मांग करके दाता के वविरण तक पहुँच सकती है।

◦ इसका मतलब यह है कि सत्ता में बैठी सरकार इस जानकारी का लाभ उठा सकती है और **स्वतंत्र व नष्पिक्व चुनाव** को बाधति कर सकती है।

#### ■ क्रोनी कैपटिलज़िम:

◦ चुनावी बॉण्ड योजना राजनीतिक चंदे पर पहले से मौजूद सभी सीमाओं को हटा देती है और प्रभावी रूप से अच्छे संसाधन वाले नगिमों को चुनावों के लिये धन देने की अनुमति देती है जिससे क्रोनी कैपटिलज़िम का मार्ग प्रशस्त होता है।

◦ क्रोनी कैपटिलज़िम एक आर्थिक प्रणाली है जो उद्योगपतियों और सरकारी अधिकारियों के बीच घनषिठ, पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों की वशिषता है।

## आगे की राह

■ **भ्रष्टाचार** के दुषचक्र को तोड़ने और लोकतांत्रिक राजनीतिक गुणवत्ता की कमी के लिये साहसिक सुधारों के साथ-साथ राजनीतिक वित्तपोषण के प्रभावी वनियमन की आवश्यकता है।

■ संपूरण शासनतंत्र को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने हेतु मौजूदा कानूनों में खामियों को दूर करना आवश्यक है।

■ मतदाता जागरूकता अभियान पर्याप्त बदलाव लाने में भी मदद कर सकते हैं।

◦ यदि मतदाता उन उम्मीदवारों और पार्टियों को अस्वीकार करते हैं जो उन पर अधिक खर्च करते हैं या उन्हें रशिवत देते हैं तो इससे लोकतंत्र एक कदम और आगे बढ़ेगा।

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/electoral-bonds-9>